# सख्त रुख से हरकत में सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के पेराई से तौबा करने वाले कड़े रुख से लखनऊ से दिल्ली तक खलबली मच गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने आनन-फानन में पिछले साल के गन्ना मूल्य को ही घोषित कर दिया। वहीं, दिल्ली में प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद मसले का हल ढूढ़ने के लिए केंद्र के दिग्गज मंत्रियों की बैठक बुला ली गई। चीनी उद्योग की मुश्किलें सुलझाने के लिए एक खास पैकेज पर लंबी चर्चा हुई।

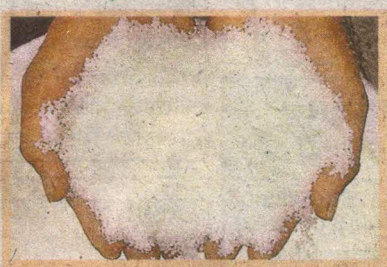

कृषि मंत्री शरद पवार की अध्यक्षता में वित्तमंत्री पी चिदंबरम और विमानन मंत्री अजित सिंह के साथ वाणिज्य व खाद्य सचिवों की बैठक हुई। इसमें चीनी उद्योग को आर्थिक संकट से उबारने पर विचार-विमर्श किया गया। इससे पूर्व चीनी मिल मालिकों ने पवार से मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। मंत्रियों की बैठक में जिस राहत पैकेज पर चर्चा हुई, उसमें उन्हें बैंकों से रियायती कर्ज दिलाने पर सहमति बनी। बैंक लोन पर ब्याज सब्सिडी देने का मसौदा तैयार किया गया। ब्याज सब्सिडी की भरपाई चीनी विकास निधि (एसडीएफ) से किए जाने का प्रस्ताव है। दूसरी ओर मिलों को रियायती कर्ज की सीमा उसकी ओर से जमा कराए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क से तय होगी। जितना उत्पाद शुल्क जमा कराया गया होगा, उतनी मात्रा में ही रियायती ऋण दिए जाने का प्रस्ताव है। चीनी निर्या करने वाली मिलों को ड्यूटी ड्रॉ बैक की सीमा व 1.3 फीसद से बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके अलाव कच्ची चीनी (रॉ शुगर) आयात करने वाली मिलों वे लिए निर्यात करने की अधिकतम अवधि 18 महीने से घटाकर तीन माह की जा सकती है। इस कदम पर भी चर्चा की गई, लेकिन मसौदे के किसी भी उपाय पर अंतिम फैसला नहीं किया जा सका। सूत्रों की मानें तो इन उपायों पर अगले एक सप्ताह में कोई निर्णय लिया जा सकता है। इस बैठक से पूर्व दोपहर में ही पवार से हुई मुलाकात में भारी घाटा और गन्ना मूल्य भुगतान संकट से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के चीनी मिल मालिकों ने मुश्किलों से उबारने की गुहार लगाई। उन्होंने चीनी का स्टॉक खाली करने और आर्थिक मुश्किलों के बारे में पवार को विस्तार से बताया। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) ने बैंक लोन मिलने की दिक्कत, ब्याज दर के भुगतान की कठिनाई और कच्ची चीनी के आयात से घरेलू बाजार के बिगड़ते संतुलन का जिक्र किया।



**चीनी उद्योग का संकट-**

- प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद केंद्र के मंत्रियों की बैठक में हुआ विचार

Dainik Jagaran

2/11/13